IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत की सामरिक परिदृश्य में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा एवं चीनी संकट

1. अवनीश कुमार शुक्ला
शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान विभाग
डी.एस.एन. कॉलेज उन्नाव
2. डॉ. मानवेन्द्र सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग डी.एस.एन. कॉलेज उन्नाव

शोध सार-

यह शोध पत्र सामरिक परिदृश्य में भारत और चीन के संबंधो का भौगोलिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक मानदंडों पर व्याख्यायित करने पर आधारित हैं। इसके तहत यह बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे चीन ने भारत को भौगोलिक सीमा विवादों में उलझा रखा है और साथ ही उसके अन्य पडोसी राष्ट्रों को चीन ने अपनी आर्थिक ऋण –जाल में फंसा रखा है ताकि वह भारत की सुरक्षा प्रणाली को अस्थिर करके वैश्विक स्तर पर भारत के कद को छोटा कर सके। इस शोध पत्र में चीन की महत्वपूर्ण वन बेल्ट वन रोड परियोजना का और पडोसी देशों पर इस योजना के फलस्वरुप उत्पन्न चीनी ऋण–जाल के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य बिंदु - ऋण –जाल, वन बेल्ट वन रोड, मार्शल प्लान।

किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से बात की जाए तो यह उसकी सीमाओं से लगे पड़ोसी राज्यों और उनमे परस्पर संबंधो से निश्चित होता है की उस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा चिंताजनक है अथवा नहीं| उदाहरणार्थ – बात अगर हम अमेरिका – कनाडा की करें तो दोनों देशों के मध्य आज तक कभी –भी कोई गंभीर सीमा विवाद मसले नहीं हुए हैं। इसीलिए यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी कोई गंभीर बात नहीं है। भारत ,भूटान एवं नेपाल के मध्य भी ऐसा वर्षों से चला आ रहा है।

परन्तु बात अगर पडोसी देशों के मध्य ख़राब रिश्तों की हो तो , इजराइल –फिलिस्तीन ,ईरान –इराक ,भारत –चीन , भारत –पाकिस्तान आदि मुद्दे सदैव प्रासंगिक बने रहे हैं।

वर्तमान में दक्षिण एशिया को लेकर ऐसी ही असुरक्षा की भावना प्रसार कर रही है चूँकि भारत दक्षिण एशिया का केंद्र स्थल है इसीलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला प्रासंगिक होना स्वभाविक है । अगर भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें तो इनमें चीन भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है ।चूँकि चीन ने हाल ही के दो दशकों में

१० % से अधिक की आर्थिक वृद्धि से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है तो उसका अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा पालना स्वभाविक है ।

वर्तमान सामरिक परिदृश्य की बात करे तो भारत की भौगोलिक , आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिए चीन की चुनौती संकट उत्पन्न कर रही है ।अगर बात भौगोलिक चुनौती की कि जाये तो हाल ही के बीते दशक में चीन ने कई भौगोलिक सीमा अतिक्रमण किए जिससे भारत की भू –सम्प्रभुता का हनन हुआ है।

2013 देपसांग गतिरोध – भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, अक्साई चीन है । चीन का दावा है कि यह इलाका शिनजियांग का हिस्सा है, जबकि भारतीयों का मानना है कि यह इलाका जम्मू–कश्मीर का हिस्सा है । लेकिन 2011 में चीनी सैन्य बलों ने विवादित क्षेत्र में 18 किमी में प्रवेश किया ताकि "बंकरों के आकार में ढीले पत्थरों से बनी 17 संरचनाओं" को नष्ट किया जा सके । 15 अप्रैल 2013 की रात के दौरान, 50 चीनी सैनिकों की एक प्लाटून ने दौलत बेग ओल्डी के पास राकी नाला की घाटी में चार तंबुओं में एक शिविर स्थापित किया । भारतीय बलों ने चीनी उपस्थिति का जवाब देते हुए 300 मीटर (980 फीट) दूर जल्दी से अपना शिविर स्थापित किया । यह विवाद 5 मई को हल हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने मामले को वापस ले लिया था।

चुमार स्टैंड–ऑफ: अप्रैल – मई 2013– दौलत बेग ओल्डी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कुछ घंटों बाद, वे लद्दाख के चुमार इलाके में वापस आ गए, और वहां जमीन पर अपने टेंट गाड़ दिए । चुमार हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे जम्मू–कश्मीर के लद्दाख इलाके का अंतिम गांव है। चुमार भारत और चीन के बीच विवाद की मुख्य कड़ी रहा है, बाद में दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करने लगे।

इस बार चीनी सैनिक भारतीय बलों द्वारा लगाए गए टिन शेड संरचनाओं पर आपत्ति जताते हुए वहां आए और लगभग पीएलए के 300 सैनिकों ने चुमार में डेरा डाल दिया था। चीनी सैनिकों ने कहा कि पिछले गतिरोध के दौरान हुए समझौते के अनुसार, भारत को उन टिन शेडों को ध्वस्त करना पड़ेगा , जिन्हें भारतीय सैनिकों ने बनाया है । बाद में दोनों देशों के कूटनीतिज्ञों ने आपसी बातचीत द्वारा मसले को हल कर लिया बाद में चीनी सैनिकों ने 5 मई को अपने टेंट को तोड़ दिया और फिर भारतीय बलों ने टिन शेड को हटा दिया।

डेमचोक गतिरोध : सितंबर 2014 – डेमचोक गतिरोध 10 सितंबर, 2014 को शुरू हुआ जब भारतीय गश्ती दल ने पाया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने के लिए भारी मशीनरी तैनात की थी , इसके विरोध में भारतीय सैनिक भी चीनी सैनिकों के सामने डेरा डालकर बैठ गए । यह विरोध तब तक चलता रहा जब शी–जिनपिंग और मोदी जी दोनों आपस में मिले , बाद में चीनी सैनिकों ने अपना डेरा हटा लिया ।

डोकलाम विवाद– जून 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई । इसका प्रमुख कारण चीन द्वारा डोकलाम से लेकर चुम्बी घाटी तक सड़क का निर्माण है, चूंकि यह क्षेत्र भूटान की संप्रभुता में आता है जिस पर भारत ने भूटान का पक्ष लेते हुए चीनी सैनिको को पीछे जाने पर मजबूर किया | भारत यहाँ इस बात से चिंतित था की यदि चीन इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है तो भारत के मध्य क्षेत्र को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला एक मात्र राजमार्ग सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ से सिर्फ 50 किमी दूर रहेगा जो भारत की संप्रभुता पर खतरा है |

गलवान घाटी सैनिक विवाद जून 2020 – हाल ही में चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी में आक्रमण कर दिया था जिसमें भारतीय और चीनी सैनिक हताहत हुए | इसका मुख्य कारण गलवान नदी और श्योक नदी से होकर दौलत बेग ओल्डी इंडियन एयर फोर्स बेस सेक्टर तक जाने वाला सड़क मार्ग है जिसका निर्माण भारत कर रहा है |

अगर बात भारत की आर्थिक सुरक्षा और चीनी चुनौतियों की कि जाए तो उस पर चीन की आर्थिक साम्राज्यवाद की कूटनीति का जिक्र करना बेहद आवश्यक है ।

चीनी अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (अमेरिका प्रथम) । चूँकि भारत और चीन दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र है , और दोनों राष्ट्रों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलें है जो दोनों देशों के किसी भी भू –क्षेत्र पर आसानी से हमला कर सकती है , इसीलिए चीन सीधी टक्कर से बचकर अपनी आर्थिक साम्राज्यवाद की कूटनीति के द्वारा भारत को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है | चीन की आर्थिक साम्राज्यवाद की कूटनीति का सबसे प्रमुख उदहारण 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गयी महत्वाकांक्षी परियोजना **वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव** जिसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया रीजन के प्रमुख छोटे विकासशील देशों को आर्थिक रूप से अपने अधीन किया जा सके ।

इसमें उसने पाकिस्तान ,नेपाल ,श्रीलंका और हॉल ही में म्यांमार को भी शामिल कर लिया है और भारत को भी उसने कई बार इस परियोजना में शामिल होने का आग्रह किया है| परन्तु भारत ने इसमें शामिल न होने का फैसला लेकर दूरदर्शी कूटनीति का प्रदर्शन किया है, भले ही इसका कारण यह रहा हो कि चीन का पाकिस्तान को जाने वाला **चाइना–पाक कॉरीडोर** विवादित पाक अधिकृत क्षेत्र से होकर जा रहा है| यह कारण तो सिर्फ तात्कालिक है ,अगर यह कारण न भी होता तब भी भारत इसमें शामिल नहीं होता और इसी कारण चीन भारत पर दबाव डालने के लिए अनेक प्रयास करता रहता है|

चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान प्रमुख साझेदार है| चीन ने अपनी 60 अरब डॉलर की इस परियोजना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चाइना –पाक कॉरीडोर के तहत निवेश किया हुआ है | इसके तहत चीन के शिंजियांग प्रान्त को ग्वादर बन्दरगाह तक रेलवे और सड़क के माध्यम से जोड़ना तथा ग्वादर पोर्ट को विकसित करना है|

इससे चीन को दो रणनीतिक फायदे सीधे तौर पर हो रहे है ,पहला –चीन पाकिस्तान में अरबो का निवेश करके पाकिस्तान को आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर बना रहा है| पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है की वो चीन के बड़े कर्ज को चुका पाये | दूसरा – वह पकिस्तान में अपनी सामरिक पहुँच से भारत को पश्चिम की तरफ से चुनौती दे सकेगा | यहाँ भी चीन की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है|

हाल ही में कुछ यूरोपीय कंपनियों ने चीन पर उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एवं चाइना –पाक कॉरीडोर में पारदर्शिता नहीं रखने एवं परियोजना में अनियमितता का आरोप लगाया है |

"चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव एक चीनी मार्शल प्लान है जिसका प्रयोग ऋण –जाल कूटनीति के लिये एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है," **यूरोपीयन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना रिपोर्ट 2020** |

इसके अलावा चीन दक्षिण एशियाई देशों को लम्बे समय तक के लिए सॉफ्ट लोन देता है और बदले में इन देशों को यह पैसा उन प्रोजेक्ट पर लगवाता है । जिनसे चीन के हित साधित हो सके और बाद में सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रोजेक्ट अंततः असफल सिद्ध होते है । ऋण लेने वाला देश ऋण –जाल में फंस जाता है बाद में चीन उस देश की घरेलू राजनीति में दखल देने लगता है, इसका सबसे अच्छा उदहारण चीन द्वारा निर्मित **हम्बनटोटा** बंदरगाह जो श्री–लंका के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है |

भारत ने दक्षिण हिन्द महासागर को परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र बनाने के बारे में सोंचा तो चीन ने संकीर्ण मानसिकता वाले महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति शासन काल में श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में हंबनटोटा पोर्ट बनाया तथा इसमें बहुत

बड़ा निवेश (क़र्ज़) किया| परन्तु जिस उद्देश्य के लिये यह बनाया गया था वह पूरा नहीं हो सका और **हम्बनटोटा प्रोजेक्ट** पूरी तरह फेल हो गया | श्रीलंका की सरकार मुनाफा कमाने की जगह चीन के कर्ज में डूब गयी | 2015 के चुनाव में राजपक्षे की हार हुई और चीन की अपेक्षा भारत की ओर झुकाव रखने वाले मैथिलीपाला सिरीसेना राष्ट्रपति बने | परन्तु श्रीलंका की सरकार के पास कर्ज को चुकता करने का कोई और विकल्प नहीं बचा और मजबूरन चीन को 99 साल की लीज पर बन्दरगाह को देना पड़ा | यह भारत की रणनीतिक हार और भूराजनीतिक राष्ट्रीय खतरा है । चीन जब चाहे तब वहां परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर सकता है |

भारत के लिए चिंता तब और बढ़ जाती है कि फिर से चीन के सहयोगी महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमन्त्री और उनके भाई गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए है और चीन अब पहले से अधिक सक्रिय हो गया है| भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे वह हिन्द महासागर में चीन के प्रभाव को रोके |

हॉल ही में श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है| श्री लंका में भीषण महंगाई , तेल संकट ,बिजली संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो गयी है , लोग महंगाई के विरोध में राजधानी की सड़कों पर उतर आए है | श्रीलंका की सरकार ने हालत पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल लगा दिया है |

श्रीलंका की जितनी जीडीपी है उससे अधिक उस पर वैश्विक कर्ज का बोझ है । अकेले चीन का 5 बिलियन ऋण उस पर है , और चीन ने बड़ी चालाकी से इस द्वीप राष्ट्र को अपने ऋण –जाल में फसांकर अपनी आँखें मूँद ली है|

इसके अलावा चीन ने अपनी आर्थिक साम्राज्यवादी कूटनीति जिसे संक्षेप में चीनी मार्शल प्लान कहा जाता है , का प्रयोग भारत के संवेदनशील पूर्वोत्तर पड़ोसी देश म्यांमार में किया है | दक्षिण एशिया में बात अगर म्यांमार की कि जाये तो यह देश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और हाल ही में 19 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति ने म्यांमार में कदम रखा है | राष्ट्रपति जिनपिंग ने अभी –२ म्यांमार का दौरा करके 33 समझौते किये जिनमें महत्वाकांक्षी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में म्यांमार की हिस्सेदारी भी है|

सामरिक स्तर पर इसके कई कारण हो सकते है जिनमे एक कारण मानवाधिकार के मुद्दे पर दोनों देशो का अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर कठघरे में होना ,क्यूंकि जहां म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर परेशान है वहीं चीन भी अपने देश के शिंजियांग प्रान्त के उईग़ुर अल्पसंख्यक मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर परेशानी में है, अतः दोनों ने बचाव के लिए एक दूसरे का साथ देना उचित समझा है |

हालांकि चीन का उद्देश्य कुछ और ही है । म्यांमार भारत का पूर्वोत्तर में स्थित प्रवेश द्धार है और म्यांमार को भी चाइना मार्शल प्लान रणनीति के तहत अपने ऋण –जाल में फंसाकर भारत को पूर्वोत्तर से चुनौती देना है | इसके लिये चीन ने म्यांमार के लिये **चीन –म्यामांर इकोनॉमिक कॉरिडोर** परियोजना लांच की है जिसमें चीन के युन्नान प्रान्त को म्यांमार के मांडले से रेल और सड़क से जोड़ा जाना है| इस नए कॉरिडोर से चीन अपने दक्षिण –पश्चिम क्षेत्र को हिंद महासागर से जोड़ेगा इसके साथ –2 और भी विकासवादी परियोजनाओं पर अरबो डॉलर निवेश किया जायेगा |

चीन अपनी इन्हीं आर्थिक ऋण –जाल कूटनीतियों के द्वारा भारत के चारो ओर स्थित पड़ोसी देशों पर नियंत्रण करके भारत को चुनौती दे रहा है |

संदर्भ सूची (Reference)-

Kumar, Sanjeev, (2019). " China's south Asia policy in the ' New Era '". *India Quarterly: A journal of International Affairs*,75 (2),137- 154 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10. 1177/0974928419841769

Malik, Mohan, J, (2010). " South Asia in China's foreign relations ". *Global change, peace & security*, 13 (1), 73-90 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1323910012003605.

European, Union, Chamber of commerce in china, (2020). " The Road less travelled : European involvement in china's belt and road initiative:report.. https://www. europeanchamber .com.cn/en/publications-belt-and-road-initiative .

Srinivasan, Meera, " China stands by Sri lanka :Wang Yi. " The hindu, 14 January (2020) https://www.thehindu.com/news/international/china-stands-by-sri-lanka-wang-yi/article30569347.ece

Bhatia, Rajiv. " Myanmar's growing dependence on China " the hindu, january 23 (2020). https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/myanmars-growing-dependence-on-china/article30627576.ece

Haidar, Suhasini, " In south asia , be the Un-China ", the hindu, august 12 (2017). https://www.thehindu.com/opinion/lead/in-south-asia-be-the-un-china/article19476384.ece

Karuna, V, (2018) " China's South Asia policy under Xi Jinping: India's strategic concerns " Central European Journal of International and Security Studies 12(2):8-29 https://www .researchgate.net/publication/327060956_China's_South_Asia_policy_under_Xi_Jinping_India's_strategic_concerns

पंत, वर्धन, हर्ष (2012) " भारतीय सुरक्षा एवं विदेश नीति " ,प्रभात प्रकाशन ,नई दिल्ली पंत , पुष्पेश (2019), " 21 वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ", टाटा मैक्ग्रा हिल्स,चेन्नई पृ0 सं0 IV.21, IV22.

सीकरी , राजीव ,(2009) " भारत की विदेश नीति : चुनौती और रणनीति ",सेज पब्लिकेशन ,नई दिल्ली पृ0 सं0 67-67,,